नहीं सुधरेगा पाकिस्तान

विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को भले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी भलमनसाहत कहा हो, पर उनका और उनकी सेना का इरादा भारत के साथ अमन-चैन से रहने का कतई नहीं है. जम्मू-कश्मीर से लगी नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की लगातार गोलाबारी यही इंगित करती है. पुलवामा की घटना के बाद अहम देशों और वैश्विक मंचों से भारत को मिला व्यापक समर्थन उसे रास नहीं आ रहा है. पाकिस्तानी धरती पर बने आतंकी गिरोह जैशे-मोहम्मद के ठिकाने को निशाना बना कर भारत ने यह भी जता दिया है कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है. बौखलाहट में जब पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों के जरिये घुसपैठ की कोशिश की, तो उसे करारा जवाब मिला. विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में भी उसे भारतीय कूटनीति क्षमता और अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने झुकना पड़ा. पाकिस्तान को यह बखूबी पता है कि न तो युद्ध में और न ही कूटनीति में वह भारत का सीधा सामना कर सकता है. ऐसे में उसके पास आतंक, घुसपैठ और युद्धविराम के उल्लंघन की पुरानी नीति पर लौटना पड़ा है. अगर यह मान भी लिया जाए कि इमरान खान दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करना चाहते हैं, तो फिर उनकी कथनी और करनी में इतनी बड़ी खाई क्यों है? आज दुनिया उनसे यही सवाल पूछ रही है कि पुलवामा हमले के बाद उन्होंने आतंकी गिरोहों और सरगनाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के पक्ष में बयान लगातार क्यों आते रहे? आखिर किसकी शह पर आतंकी अब भी सक्रिय हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन के सिलसिले को रोकने के लिए उन्होंने क्या पहलकदमी की है? दरअसल, इमरान खान भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह भारत में अस्थिरता और अशांति फैलाने की नीति पर चल रहे हैं. ऐसा ही पाकिस्तान अपने अन्य पड़ोसी देशों- अफगानिस्तान और ईरान- के साथ भी कर रहा है. पिछले साल युद्धविराम के उल्लंघन की करीब तीन हजार घटनाएं हुई हैं. पुलवामा के बाद तनाव के युद्ध में बदल जाने की आशंकाओं के बाद भी इनमें कमी नहीं आ रही है. कश्मीर के भीतर अपने घटते प्रभाव से भी पाकिस्तान बेचैन है. पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना के 111 रिक्त पदों के लिए लगभग तीन हजार कश्मीरी युवकों का आवेदन इंगित करता है कि कश्मीरी युवा शांति और सुरक्षा के साथ देश की मुख्यधारा के साथ विकास की राह पर बढ़ने का आकांक्षा रखता है. कुछ दिनों पहले संपन्न पंचायत चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था. रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, खेल-कूद आदि से जुड़ीं सरकारी पहलों में कश्मीरी जनता की भागीदारी बढ़ रही है. इन प्रयासों को पाकिस्तानी सरकार और सेना आतंक, अलगाव और हमलों से कमजोर करना चाहते हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सकें. ऐसे में भारत को कश्मीर में और सीमा पर चौकस और आक्रामक बने रहने की आवश्यकता है.

पाकिस्तान को यह बखूबी पता है कि न तो युद्ध में और न ही कूटनीति में वह भारत का सीधा सामना कर सकता है.

सैन्य कार्रवाई की नयी लक्ष्मण रेखा

आशुतोष चतुर्वेदी
प्रधान संपादक, प्रभात खबर
ashutosh.chaturvedi
@prabhatkhabar.in

पाकिस्तान में कितने अंदर घुस कर कार्रवाई की जाए, इसकी जो लक्ष्मण रेखा भारत ने खींच रखी थी, वह इस बार तोड़ दी गयी. पीएममोदी ने जो लकीर खींच दी है, कोई भी भारतीय सरकार उससे पीछे नहीं हट पायेगी.

विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वापसी से पूरा देश प्रसन्न है. होना भी चाहिए. अभिनंदन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया था, लेकिन इस संघर्ष में उनका मिग-21 विमान भी गिर गया और वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा पहुंचे. पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन भारतीय व अंतरराष्ट्रीय दबाव काम आया और आखिरकार वह रिहा हो गये. जांबाज सैनिक की वापसी को पाकिस्तान ने काफी उलझाये रखा. ऐसी सूचनाएं हैं कि पाकिस्तानी सेना के कुछ जनरल और आइएसआइ के कुछ अफसर अभिनंदन की रिहाई को लेकर नाखुश थे. आखिरी वक्त तक वे अड़चने खड़ी करते रहे. दबाव देकर अभिनंदन से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया गया और रिहाई से ठीक पहले उसे पाकिस्तानी मीडिया को रिलीज कर दिया गया. इस संघर्ष में पाकिस्तान का एक एफ-16 विमान अभिनंदन ने मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है. पाकिस्तानी विमान एफ-16 के पायलट को भीड़ ने भारतीय समझ कर पीट-पीट कर मार डाला. सूचना क्रांति के इस युग में कुछ भी छुपा नहीं है. जो एफ-16 विमान मार गिराया गया, वह पाक वायुसेना की 19वीं स्क्वाड्रन का पायलट शहजाजुद्दीन उड़ा रहा था. भारतीय सेना की यह परंपरा रही है कि वह अपने शहीद सैनिकों के नाम कभी नहीं छुपाती, दूसरी ओर पाकिस्तान हमेशा अपने सैनिकों की मौत की बात छुपाता है. अगर आपको याद हो, करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जो भी जवान शहीद होते थे, पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता था, लेकिन पाकिस्तान सेना अपने सैनिकों की मौत की बात कभी नहीं कबूलती थी और दबे-छुपे तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था.

भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की लगातार कोशिशें करता आया है, लेकिन कभी कामयाब नहीं मिली. कभी मुंबई में हमला हुआ, तो कभी उड़ी, पठानकोट और पुलवामा में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब भी वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि भारत सबूत दे कि हमले में पाकिस्तानी संगठन शामिल हैं, तो कार्रवाई करेंगे, जबकि हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद ने ली है. जैशे मोहम्मद पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन है. इसके सरगना मसूद अजहर का ठिकाना पाकिस्तान ही है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी स्वीकार कर रहे हैं कि मसूद पाकिस्तान में है. कह रहे हैं कि वह बीमार है, उसका इलाज चल रहा है. इस बार आत्मघाती हमलावर का वीडियो सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें वह खुद कह रहा है कि वह जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है. हमले के बाद पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी. इसके बाद भी पाकिस्तान को किन सबूतों की जरूरत है, यह समझ से परे है. मुंबई, पठानकोट और उड़ी सबके सबूत दिये गये हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की. जैशे मोहम्मद और लश्करे तैबा के आतंकवादी वहां खुलेआम घूमते हैं. मैंने पहले भी लिखा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान सेना के मुखौटा भर हैं. वह सेना की नीतियों से इधर-उधर जाने की सोच भी नहीं सकते. पाकिस्तानी सेना के सहयोग से ही आतंकवादी संगठन फलते-फूलते हैं और वह उन्हें नियंत्रित करती है. सेना ही उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करती है. शांति की किसी भी पहल को वह कामयाब नहीं होने देती. दिलचस्प तो यह है कि पाकिस्तान अब इमरान खान को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है. वहां की संसद में सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया है कि इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, जबकि पाकिस्तान में शांति की बात करने वाले राजनेता ज्यादा दिन नहीं चलते हैं.

दरअसल, 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत में मानस बन गया था कि पाक अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है. दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना ने मान लिया था कि भारत को पारंपरिक युद्ध में हराना संभव नहीं है और उन्होंने आतंकवादियों का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया. 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद तो भारत ने पारंपरिक युद्ध के विकल्प पर विचार करना ही छोड़ दिया और सेना के आधुनिकीकरण का काम लगभग बंद कर दिया. रही-सही कसर रक्षा खरीद में घोटालों के सामने आने के बाद पूरी हो गयी. दूसरी ओर परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान ने खौफ का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि हम उसके झांसे में आ गये. मौजूदा संघर्ष को देखें, तो अभिनंदन तीन दशक से अधिक पुराने मिग-21 विमान से पाकिस्तान के एफ-16 विमान का मुकाबला कर रहे थे, जिसे संग्रहालय में रख दिया जाना चाहिए था. सैन्य साजोसमान की खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो राफेल विमान पर जम कर राजनीति हो रही है, उसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है. इस संघर्ष के दौरान कई नयी बातें सामने आयीं. एक संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध मैदान में हुआ. दूसरा भारत और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया में लड़ा जा रहा है. इस हो-हल्ले में भारतीय कार्रवाई का पूरा विश्लेषण नहीं हो पाया है. पुलवामा हमले के बाद के घटनाक्रम ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष की नयी लक्ष्मण रेखा खींच दी है. पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायु सेना ने जैशे मोहम्मद के जिस कैंप को निशाना बनाया वह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के बालाकोट में स्थित है. पहले इस बात को लेकर भ्रम था कि हमला पुंछ के नजदीक बालाकोट पर हुआ है या फिर खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के बालाकोट में, लेकिन जल्द ही यह बात साफ हो गयी. यह बालाकोट पाकिस्तान के मानशेरा जिले का हिस्सा है. भारतीय लड़ाकू विमान वहां कार्रवाई कर सकुशल वापस आ गये और पाकिस्तानी वायु सेना सोती रही. उड़ी के हमले के बाद भारतीय सेना ने सीमा के नजदीक के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था. इसके आगे सेना नहीं बढ़ी थी, लेकिन पहली बार यह लक्ष्मण रेखा पार की गयी है. इस विषय पर बहस हो सकती है कि कितने आतंकवादी मारे गये, लेकिन पाकिस्तान में कितने अंदर घुस कर कार्रवाई की जाए, इसकी जो लक्ष्मण रेखा भारत ने खींच रखी थी, वह इस बार तोड़ दी गयी. और यह जान लीजिए कि एक बार बंधा टूटा तो फिर बहाव को कोई नहीं रोक सकता है. अब पाकिस्तान की ओर से किसी भी आतंकवादी घटना का जवाब भारत पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को निशाना बना कर दे सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लकीर खींच दी है, कोई भी भारतीय सरकार उससे पीछे नहीं हट पायेगी.

क्या हों आम चुनाव के मुद्दे

योगेंद्र यादव
अध्यक्ष, स्वराज इंडिया
yyopinion@gmail.com

संभावना बन रही है कि 2019 का चुनाव गांव, किसान और खेती या फिर युवा शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पर न होकर राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर केंद्रित हो जाये. ऐसा होता है, तो यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं.

पुलवामा हमले के अगले ही दिन मैंने राष्ट्रीय सहमति का एक प्रस्ताव रखा था. सोच यह थी कि आतंकी और उसके सरगना हमें एक-दूसरे से लड़ने-भिड़ने और भारतीय राजनीति को पटरी से उतारने के अपने मंसूबे में कामयाब ना हों. संकट के समय राष्ट्रीय एकता ही आतंकियों को सबसे करारा जवाब है.

मेरे प्रस्ताव के तीन सूत्र थे. पहला तो यह कि सरकार विपक्ष को विश्वास में ले. राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता को बनाये रखते हुए घटना और उसके प्रतिकार की सोच को वह विपक्ष के चुनिंदा नेताओं के साथ साझा करे. दूसरा, विपक्ष इस मौके का इस्तेमाल सरकार के छिद्रान्वेषण के लिए न करे और संकट समाप्त होने तक इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना न करे. तीसरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमति बनायें कि वे पुलवामा हमले और उसके प्रतिकार से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को चुनावी मुद्दा नहीं बनायेंगे. कश्मीरियों के खिलाफ वारदातों के बाद मैंने चौथा सूत्र भी जोड़ा: इस मौके पर देश के किसी भी व्यक्ति या समुदाय को हिंसा या नफरत का शिकार नहीं बनने दिया जायेगा.

इस प्रस्ताव को आम लोगों से बहुत समर्थन मिला, लेकिन बड़ी पार्टियों ने इसे आधे मन से सुना. बालाकोट में जवाबी हमले के बाद इस बात पर राष्ट्रीय सहमति की जरूरत और बढ़ गयी. यह तो स्पष्ट था कि पुलवामा से शुरू हुआ सिलसिला बालाकोट पर नहीं रुकेगा. इमरान खान और पाकिस्तानी सेना दोनों को अपनी इज्जत और सत्ता बचाये रखने के लिए कुछ जवाबी कार्रवाई करनी ही थी. पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि बालाकोट में जान-माल की हानि नहीं हुई. जाहिर है ऐसे में रोज नये तथ्य आयेंगे और उत्तर-प्रत्युत्तर की चर्चा होगी.

इस बार इस मुद्दे के राजनीतीकरण की संभावना और भी ज्यादा है. वैसे तो वायु सेना के हमले के बाद सभी दलों ने सुरक्षाबलों को बधाई दी, कम-से-कम पहले दिन आरोप-प्रत्यारोप शुरू नहीं हुए. लेकिन पहले दिन ही राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री के भाषण से इस सवाल पर होनेवाली राजनीति की झलक मिल गयी. विपक्ष के नेताओं ने भी आलोचना शुरू कर दी है. आमतौर पर ऐसे में सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर सहमति नहीं असहमति चाहेगी, ताकि यह चुनावी बहस का केंद्र बन सके.

कुल मिला कर यह संभावना बन रही है कि 2019 का चुनाव गांव, किसान और खेती या फिर युवा शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पर न होकर राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर केंद्रित हो जाये. ऐसा होता है, तो यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं.

राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल का राजनीतीकरण करने के कई खतरे हैं. एक तो सरकार और सुरक्षाबलों पर अनावश्यक दबाव बनेगा. देश में युद्धोन्माद का माहौल बनेगा. देश के भीतर व्यक्तियों या समुदायों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुपचाप से दीर्घकालिक कदम उठाने की बजाय शोरगुल करने का आग्रह प्रबल होगा. दूसरी बात यह भी है कि राजनीतिक दल की छींटाकशी से अनावश्यक सवाल उठेंगे. क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के कर्ता-धर्ता लोगों में से कुछ को पुलवामा की दुर्घटना का पूर्वाभास था? क्या उसे टाला नहीं जा सकता था? क्या बालाकोट में आतंकी कैंप को नष्ट करने और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के दावे वाकई सही हैं? ये सब वाजिब प्रश्न हैं, जिन्हें चुनावी दंगल में उछालने से इनका सही उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि सुरक्षा बलों का मनोबल ही कमजोर होगा.

लोकसभा के चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रित करने से हमारे लोकतंत्र को भी नुकसान होगा. पांच साल के बाद केंद्र सरकार का हिसाब करने और उससे जवाब मांगने का यह अवसर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के मूल्यांकन का समय है, यह सेकुलर ढांचे पर हुए असर को जांचने का समय है, यह अंतिम व्यक्ति को किये गये वादे के हिसाब-किताब का समय है. इस बार यह संभावना बनी थी कि लोकसभा चुनाव खेती, गांव, किसान, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे जमीन से जुड़े मुद्दों पर होगा. अगर इन सबको भूल कर सिर्फ पाकिस्तान और आतंकियों के सवाल पर चर्चा होने लगी, तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पटरी से उतर जायेगी. ऐसा हुआ, तो हमारे लोकतंत्र की भी वही हालत हो जायेगी जो नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान की है. इन देशों में हर बार चुनाव भारत-विरोध के मुद्दे पर लड़ा जाता है और भावनाएं भड़का कर जीता जाता है. अगर हमारा 70 साल पुराना लोकतंत्र भी इसी स्तर पर उतर आता है, तो यह पुलवामा के आतंकी और उनके पाकिस्तानी आकाओं की भारत पर सबसे बड़ी विजय होगी.

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि सभी दल मिल कर यह न्यूनतम सहमति बनायें कि इस चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को राजनीतिक दंगल में नहीं घसीटा जायेगा. अगर पुलवामा और बालाकोट से शुरू हुए घटनाक्रम के बारे में कुछ सवाल हैं, अगर उसमें कुछ ऊंच-नीच हुई है, तो उसे उसकी चुनाव के बाद समीक्षा होगी, लेकिन उसे चुनावी वाद-विवाद से अलग रखा जायेगा. न कोई पार्टी देश की सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उंगली उठायेगी, न कोई नेता सुरक्षाबलों के पराक्रम का श्रेय लेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिक कार्रवाई और जवानों की शहादत पर किसी भी तरह की राजनीति करना देशप्रेम का लक्षण नहीं है.

आपके पत्र

पुलवामा पर राजनीति न हो

विपक्ष के कई नेताओं ने जिस तरह केंद्र सरकार से पुलवामा का बदला लेने में भारतीय सैनिकों द्वारा मारे गये आतंकियों की संख्या के सबूत की मांग की है, वह बेहद ही शर्मनाक है. ऐसे लोग मुसीबत के समय साथ देने की बातें तो करते हैं, पर जब कार्रवाई की जाती है, तो अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं. नेताओं द्वारा भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है, वह उचित नहीं है. चुनाव नजदीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी मुद्दे को राजनीति से जोड़ दिया जाए. वाकई यह देश की विडंबना है कि हमें बाहरी शक्तियों के साथ-साथ भीतरी अलगाववादी शक्तियों से भी लड़ना पड़ रहा है. ये लोग अपने बयानों से आतंकियों का मनोबल बढ़ा कर रहे हैं. राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, पुलवामा को इसमें न घसीटें.

शुभम गुप्ता, धनबाद

कांटे ही कांटे !

इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बन चुका है. उसने अपनी गतिविधियों से इस बात की पुष्टि भी कर दी है. दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा, जिसे अमेरिका ने चुपचाप पाकिस्तान में घुस कर पकड़ लिया और ऐसी जगह मारा कि उसकी लाश तक का पता नहीं चल सका. भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को साफ करने की कोशिश की. आतंकियों को पनाह देने के कारण आज पाकिस्तान दुनिया के सामने नंगा भी हो चुका है. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खुद इन आतंकियों के सहारे ही सत्ता में आये हैं. वह महज दिखावे के लिए चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे हैं. दुर्भाग्य से राजनीति और कूटनीति में यह सब होता है. इसलिए इन कांटों से हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है.

वेद मामूरपुर ,नरेला

नहीं सुधरेगा पाकिस्तान

हिंदुस्तानी शौर्य और स्वाभिमान की यह नयी सुबह है. पाकिस्तान तो अपना बम और कटोरा लेकर घूमता रहेगा, जैसे पहले घूमता था, लेकिन अब उसकी नापाक हरकतों को भारत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. हमारा देश वही है, सेना वही है, दुश्मन भी वही हैं, लेकिन हमारा इकबाल मजबूत हुआ है, क्योंकि जिसके हाथ में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह मक्कार नहीं है. पहले हम अपने जान-माल का नुकसान होने पर चिल्लाते थे, तो दुनिया नसीहत देती थी कि आपसी बातचीत से मामले को निबटाया जाना चाहिए. अब हमारी खामोशी को भी दुनिया का सबसे दबंग राष्ट्र समझता है. सात समंदर पार अमेरिका हमारे स्वभाव और बदले मिजाज को ताड़ लेता है, जबकि पड़ोसी कान में तेल डाल कर सोता रहता है. पाकिस्तान की सभी जंग आतंकवादी लड़ते हैं. इसलिए आजतक पाक कोई युद्ध नहीं जीत सका. जहां दुनिया की फौजी युद्ध लड़ती हैं, वहीं पाकिस्तान की फौज राजनीति करती है.

सिद्धार्थ सिन्हा, कांके रोड, रांची

बोधि वृक्ष

सिद्ध हो जाएं

वह सब जो गतिमान है, घूम रहा है, कैसे भी हो, रुकनेवाला तो है ही. लेकिन जो स्थिर है, वह हमेशा के लिए है. अस्तित्व में कोई भी गति लगातार नहीं चलती, कोई संचार चिरकाल के लिए नहीं होता. कुछ चीजें लंबे समय के लिए हो सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं. जो गतिशील है, वह अपने आप को थका ही डालेगा, लेकिन जो स्थिर है, वह हमेशा के लिए है. हम ध्यान के रूप में जिसका प्रचार करते हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वह अंत में तो अस्तित्व का मूल, मर्म बनने के लिए, स्थिरता की ओर बढ़ना ही है. इसका अर्थ यह नहीं है कि वैसा करने के लिए आप को कोई संघर्ष करना है या बहुत प्रयत्न करने हैं. यह वैसा है कि क्या आप बेधना, प्रवेश करना सीखते हैं? यह ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रयत्नपूर्वक करना है, क्योंकि 'करना' अपने आप में गति है. गति में आप सहज रूप से आ जाते हैं, क्योंकि स्थिरता में से ही गति की प्रक्रिया जन्मी है. इस स्थिरता में से वह सतह मिलती है, जो गति है, संचार है. ऊपरी सतह पर बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, कई प्रकार के रंग हैं, बहुत सी ध्वनियां गूंजती हैं, वे सब स्थिरता के विरुद्ध नहीं होते. पर एक बार जब आप को स्थिरता का स्वाद मिल जाता है, तब आप चाहें, तो सतह से खेल सकते हैं, अन्यथा आप बस वहां होते हैं. अगर आप मूल बात नहीं जानते, यदि आप ने मर्म का स्वाद नहीं लिया है, तो आप हमेशा एक प्रकार की मजबूरी के साथ गतिमान रहते हैं. यकीन कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप के लिए, जीवन अभी कितना ज्यादा उत्साहवर्धक, आनंददायक है, एक दिन तो आप थक जायेंगे. मैं बस आशा करता हूं कि आप थककर न गिरें(मरें). आप तब गिरें, जब आप सिद्ध हो जाएं, पक जाएं, मीठे हो जाएं. एक फल पेड़ से इसलिए गिरना चाहिए कि वह पक चुका है, इसलिए नहीं कि वह थक चुका है. पकने के साथ परिपक्वता आती है, मिठास आती है, नयी संभावना आती है. अगर आप थक गये हैं और गिर जाते हैं, तो यह जीवन से सही ढंग से अलग हो जाना नहीं है.

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

पाकिस्तान में मंत्री होना

आलोक पुराणिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

मंत्री होना मुश्किल काम है और पाक में मंत्री होना बहुत मुश्किल काम है. पाक में मंत्री की आफत यह है कि हाथ में उसके कुछ न होता, पर इंटरनेशनल गालियां खाने का जिम्मा मंत्री का होता है. पाक का आतंकी-सेना गठजोड़ रात में बम फोड़कर निकल लेता है, पर गालियां मंत्री खाता है. पाकिस्तान के इमरान खान की आफत दोहरी है, आतंकी-सेना गठजोड़ के सामने उन्हें परम आतंकी दिखना है और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें परम शांतिप्रिय दिखना है. पाक सेना भेड़िया है, पाक आतंकी भेड़िये हैं, इनकी पहचान साफ है. पर लोकतंत्र की खाल ओढ़ कर इमरान खान को कभी भेड़िया दिखना है कभी मेमना दिखना है, इस चक्कर में इमरान खान ऐसे जानवर हो जाते हैं, जो हास्यास्पद लगते हैं.

इमरान कह रहे होते हैं कि हमें शांति चाहिए. तभी आइएसआइ और सेना के संयुक्त तत्वावधान में भारत में धमाके हो चुके हैं. पाकिस्तान कई मुंह वाला देश है, जिसमें एक मुंह को न पता होता कि दूसरा मुंह क्या कह गया. उसको दोमुंहा कहना अंडरस्टेटमेंट है, उसके मुंह कितने हैं- यह किसी को ना पता.

पाक का मंत्री कहता है- हमें देश में उद्योगों का विकास करना है. और विकास हो जाता है आतंकियों का. इमरान खान कहते हैं कि मुझे सबूत दो तो मैं सब सही कर दूंगा. पाकिस्तान की सरकार को अब तक यह सबूत न मिल पाया है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया और वहीं मार भी गिराया गया था. पर पाकिस्तान को कोई सबूत न मिला. इमरान खान रोज सुबह उठ कर यह सबूत तलाशते हैं कि आज मैं पीएम हूं या नहीं. पाकिस्तान में जो दिखता है, वह है नहीं. जिसे पीएम समझो वह सेना का स्टेनो निकलता है, सेना जो कहे, वह ऑर्डर नोट करता है. जिसे सेना समझो, वह आतंकियों की केयरटेकर निकलती है. जिन्हें आतंकियों का अड्डा समझो उन्हें पाकिस्तानी नेता अजहर के मदरसे बताते हैं. जिन्हें मदरसे समझो वहां बम-बंदूक बरामद होते हैं. जिन्हें मदरसों के टीचर समझो, वे अरबों-खरबों के कारोबारी निकलते हैं. जिन्हें आप कारोबारी समझो, वह सांसद निकल जाते हैं और जिन्हें आप सांसद समझो, वह आतंकी मसूद अजहर के प्रवक्ता निकल जाते हैं. पाकिस्तान क्या है, यह समझना भी कन्फ्यूजन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ज्यादा हैं या भीख के कटोरे ज्यादा हैं, यह पता लगाना भी मुश्किल है.

खैर, जिस अमेरिका को टीवी पर नार्थ कोरिया के किम कई बार उड़ा चुके थे, उसी अमेरिका के ट्रंप के साथ किम की शिखर वार्ता की खबरें हैं. टीवी खबरों के साथ वैधानिक चेतावनी लिखकर आनी चाहिए- अधिकांश काल्पनिक हैं. युद्ध के बारे में जितना सेना के अधिकारी नहीं जानते, उससे ज्यादा अब टीवी एंकर जानने लगे हैं. एक टीवी एंकर कुछ समय पहले शांति वार्ता प्रोग्राम का एंकर था, जो शांति से चलनेवाले एक जनरेटर ने स्पांसर किया था, फिर वही टीवी एंकर तोप के गोले बरसा रहा था. शो किसी धमाकेदार बैटरी ने स्पांसर किया था. एंकर कुछ भी करवा सकता है, स्पांसर बताओ.

देश दुनिया से

अमेरिका-कोरिया के बीच नहीं बनी सहमति

वियतनाम के हनोई में आयोजित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के बीच दूसरा शिखर सम्मेलन बिना किसी समझौते के केवल विचारों के आदान-प्रदान के साथ संपन्न हुआ. पिछले साल जून में सिंगापुर में दोनों देशों के बीच हुए पहले शिखर सम्मेलन के विपरीत, इस सम्मेलन के सफल होने की उम्मीद थी. पर दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो सका. हालांकि इस बैठक के बाद ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर कोरिया चाहता है कि उस पर से प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिये जायें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा कि चूंकि उत्तर कोरिया तैयार नहीं था, ऐसे में इससे अमेरिका को वह हासिल नहीं हुआ, जिससे उसे फायदा पहुंचता. साफ है कि अमेरिका वार्ता के असफल होने का दोष उत्तर कोरिया पर डालना चाहता है. लेकिन शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए, बाहरी लोग शायद ही यह विश्वास करें कि उत्तर कोरिया ने अपने ऊपर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव दिया होगा. उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने कहा कि हमने प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की बात की थी, जो बहुत यथार्थवादी प्रस्ताव था.

GLOBAL TIMES

झाओ लिक्सिन

कार्टून कोना

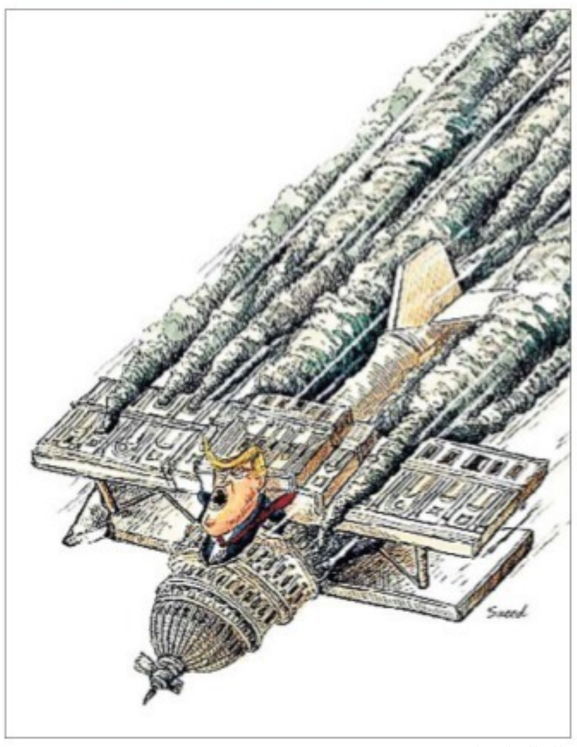

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है